VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

# TODAY'S ANALYSIS
## (आज का विश्लेषण)
## (02 July 2024)

### Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

## Important News:

- शहरी विस्तार से दिल्ली में बाढ़ का खतरा कैसे बढ़ रहा है?
- तिब्बत एयरबेस पर चीन के स्टील्थ लड़ाकू विमानों की तैनाती का भारत के लिए मतलब
- भारत रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है?
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

# शहरी विस्तार और दिल्ली में बाढ़ का खतरा:

## परिचय:

- अनियंत्रित और बिना सोचे-समझे किया गया शहरी विस्तार दिल्ली और बड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगातार शहरी बाढ़ का मुख्य कारण है।
- पिछले सप्ताह भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई हिस्से थम से गए थे। शहर भर में और एनसीआर में सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे कुछ जगहों पर घंटों तक यातायात जाम रहा। यह बारिश अभूतपूर्व थी, लेकिन बाढ़ और जलभराव अब दिल्ली के मानसून के मौसम का अभिन्न अंग बन गए हैं।

- नगर निगम अधिकारियों द्वारा नालों की अपर्याप्त सफाई जैसे कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके मूल में, दिल्ली एक और अधिक बुनियादी समस्या से ग्रस्त है।

## दिल्ली एक तेजी से बढ़ता शहर:

- उल्लेखनीय है कि दिल्ली दुनिया के सबसे तेज़ शहरी विस्तारों में से एक से गुज़र रही है। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी के डेटा के अनुसार, 1991 से 2011 तक दिल्ली का भौगोलिक आकार लगभग दोगुना हो गया है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- इस विस्तार का ज्यादातर हिस्सा नई दिल्ली के बाहरी इलाकों में हुआ है, जहां पहले ग्रामीण इलाके राजधानी के शहरी विस्तार में समा गए हैं। दिल्ली के बाहर के शहर, लेकिन एनसीआर का हिस्सा - बहादुरगढ़, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम - में भी तेजी से शहरीकरण हुआ है।
- संयुक्त राष्ट्र की 2018 में दुनिया के शहरों की डेटा बुकलेट के अनुसार, दिल्ली 2030 तक टोक्यो को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन जाएगा, जिसकी अनुमानित आबादी लगभग 39 मिलियन होगी, जो 2000 की आबादी से लगभग ढाई गुना ज्यादा है।

## शहरी विस्तार में दिल्ली की प्राकृतिक स्थलाकृति पर कम ध्यान:

- इस शहरी विस्तार ने दिल्ली की प्राकृतिक स्थलाकृति पर बहुत कम ध्यान दिया है। इंटैक के प्राकृतिक विरासत प्रभाग के प्रमुख निदेशक मनु भटनागर के अनुसार "स्थलाकृति जल निकासी पैटर्न निर्धारित करती है"।
- अगर दिल्ली के ऐतिहासिक शहरों को देखें - तुगलकाबाद, महरौली और शाहजहानाबाद से लेकर सिविल लाइंस, नई दिल्ली और कैंटोनमेंट क्षेत्र तक - सभी को सावधानी से चुना गया था और ऊँची जमीन पर बनाया गया था। इससे बारिश का पानी बाहर निकल जाता था।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- लेकिन जैसे-जैसे शहर का विस्तार हुआ, भूमि की जल निकासी क्षमताओं के संबंध में निर्माण के पीछे पर्याप्त विचार नहीं किया गया।
- इस प्रकार, उच्च-तीव्रता वाली बारिश के साथ महत्वपूर्ण अपवाह होता है और मौजूदा जल निकासी प्रणालियाँ अपर्याप्त साबित होती हैं।

**हर जगह कांक्रीटीकरण से स्थिति और भी ख़राब हुई:**

- विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली में रिज से नदी तक की भूमि ढलान लगभग 100 मीटर की है। लेकिन शहरीकरण के कारण, पानी आसानी से इस ढलान से नीचे नहीं बह सकता।
- आज, अधिकांश पानी कंक्रीट के नालों (नालियों) में चला जाता है, जिन्हें सीवेज डंप में बदल दिया गया है। निचले इलाकों में निर्माण से हालात और भी खराब हो गए हैं।
- दिल्ली के बाढ़ के मैदानों में निर्माण 1900 के दशक में ही शुरू हो गया था, जब अंग्रेजों ने नदी के किनारे रेलवे लाइन बनाने का फैसला किया था। बहुत बाद में, रिंग रोड फिर से यमुना के बाढ़ के मैदान पर बनी। पिछले कुछ सालों में, बाढ़ के मैदान का इस्तेमाल पुलों से लेकर इमारतों के निर्माण तक सभी तरह के उद्देश्यों के लिए किया गया है।

- उल्लेखनीय है कि आईटीओ-प्रगति मैदान क्षेत्र, जो सालों से बाढ़ देख रहा है, कभी एक निचला आर्द्रभूमि क्षेत्र था।
- इस अतिशय कांक्रीटीकरण के कारण वर्षा जल को मिट्टी में रिसने के लिए बहुत कम जगह बचती है, जिससे बाढ़ आ जाती है।

## दिल्ली के लिए कोई 'जल मास्टरप्लान' नहीं:

- 2008-2011 तक दिल्ली शहरी कला आयोग (DUAC) के अध्यक्ष रहे के. टी, रवींद्रन ने कहा कि शहरी योजनाकारों को 'जल मास्टरप्लान' बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'आज, भूमि को रियल एस्टेट के रूप में देखा जाता है, और नियोजन संसाधन के रूप में पानी की लगातार उपेक्षा की गई है।
- वास्तव में, किसी भी मास्टरप्लानिंग के पीछे पानी प्राथमिक प्रेरक कारक होना चाहिए। वास्तव में पिछले 70 वर्षों में शहर के स्वच्छ और अपशिष्ट जल प्रवाह को ध्यान में रखते हुए कोई व्यापक योजना नहीं बनाई गई है। यही कारण है कि 2022 में उद्घाटन की गई नई प्रगति मैदान सुरंग हर मानसून में बाढ़ में डूब जाती है।
- इसके अतिरिक्त बाढ़ को प्रबंधित करने में मदद करने वाले जल निकायों को भी व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया है। 'आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली

में लगभग 1,000 जल निकाय हैं। लेकिन जमीन पर 400 से अधिक नहीं हैं। ये 600 'गायब' जल निकाय, जो शहर में बाढ़ का प्रबंधन कर सकते थे, भर दिए गए हैं, और मूल्यवान अचल संपत्ति में बदल दिए गए हैं।

## बड़े महनगरों में बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

- जब तक हम निचले इलाकों में निर्माण बंद नहीं करते, अपने लॉन और फुटपाथों को कंक्रीट से मुक्त नहीं करते, और नालियों को ठोस कचरे से अवरुद्ध करना बंद नहीं करते, शहरी बाढ़ नहीं रुकेगी।
- शहरी बाढ़ या जल भराव की समस्या को रोकने के लिए ढाल को समझना होगा और जमीन की बनावट के साथ काम करना होगा और किसी भी शहरी किसी भी मास्टरप्लानिंग के पीछे पानी को प्राथमिक प्रेरक कारक मानना होगा।

# तिब्बत एयरबेस पर चीन के स्टील्थ लड़ाकू विमानों की तैनाती का भारत के लिए मतलब:

## चर्चा में क्यों हैं?

- तिब्बत में शिगात्से एयरबेस पर 12,408 फीट की ऊंचाई पर खड़े चीन के पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर, J20 माइटी ड्रैगन, और J10 विगोरस ड्रैगन फाइटर की हाल ही में सैटेलाइट इमेज ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है और भारत के सुरक्षा क्षेत्र में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

- इसने J20 और 4.5 पीढ़ी के भारतीय राफेल के बीच तुलना को बढ़ावा दिया है और दोनों वायु सेनाओं के माप के रूप में लड़ाकू विमानों की संख्या की तुलना की जाने लगी है।
- हालांकि, संख्या की गणना वायु शक्ति के वास्तविक सैन्य माप को नहीं दर्शाती है और इसमें कई सारे पहलु शामिल होते हैं।

## तिब्बत के अग्रिम बेस पर J20 की तैनाती के मायने:

- उल्लेखनीय है कि J20 को अमेरिकी F22 का प्रतिस्पर्द्धी माना जाता है, जिसमें लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री की आंतरिक वहन क्षमता है।
- ऐसे में तिब्बत क्षेत्र में J20 की मौजूदगी चीनी वायुसेना के उच्च-स्तरीय लड़ाकू विमानों, लड़ाकू अभियानों के लिए अपने उच्च-ऊंचाई वाले हवाई ठिकानों का उपयोग करने की इसकी क्षमता और भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई और राफेल की अग्रिम तैनाती का मुकाबला करने के लिए इस क्षेत्र में हवाई शक्ति को प्रोजेक्ट करने की इसकी बढ़ती क्षमता को दर्शाती है।
- यह एक राजनीतिक संकेत भी है कि भारत के साथ सीमा विवाद अब एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि संप्रभु हवाई क्षेत्र का भी एक मुद्दा है।

## भारत-चीन सीमा के करीब J20 की तैनाती का भारत के लिए सुरक्षा निहितार्थ:

- उल्लेखनीय है कि चीन ने भारत-चीन सीमा पर अपनी गतिशीलता और रसद सहायता को बनाए रखने के लिए लगातार एक मजबूत सीमा अवसंरचना का निर्माण किया है, बल अनुपात में सुधार करने के लिए अपनी सेना की तैनाती में

वृद्धि की है, और सीमा-वार्ता कार्य तंत्र के 29 सत्रों के बावजूद सैन्य उपस्थिति के साथ अपने राजनीतिक रुख को बनाए रखना जारी रखा है।

- ऐसे में इन विवादित क्षेत्रों में चीन द्वारा बफर जोन के निर्माण की मांगों के आगे झुकना, जाहिर तौर पर भारत के लिए विघटन के अग्रदूत के रूप में, भविष्य में हवाई बफर जोन की मांगों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है - यह चीनियों को इस क्षेत्र में भारतीय वायु सेना की उपस्थिति और संचालन को रणनीतिक रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अनुकूल है।
- यदि वर्तमान स्थिति को सावधानीपूर्वक संबोधित नहीं किया जाता है, तो सीमा के करीब अग्रिम हवाई पट्टियाँ और विवादित क्षेत्रों पर संप्रभु हवाई क्षेत्र "नो-फ्लाई जोन" बन सकते हैं, जो खुफिया, निगरानी और टोही मिशनों के साथ-साथ हवाई गतिशीलता और हवाई रसद के लिए IAF विमानों के लिए दुर्गम हो सकते हैं।

## इस स्थिति के लिए भारतीय वायु सेना की तैयारी:

- फिलहाल, भारतीय वायुसेना के चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के मुख्य बेड़े में सुखोई 30, MiG 29 और मिराज 2000 शामिल हैं, जिन्हें 4.5 पीढ़ी के राफेल के दो स्क्वाड्रनों द्वारा पूरक बनाया गया है, जो एक असममित लाभ प्रदान करता है, जिसे चीन प्राथमिकता के आधार पर बेअसर करने के लिए काम कर रहा है।

- उल्लेखनीय है कि सरकार भारतीय वायुसेना की घटती लड़ाकू वायु शक्ति सूची से चिंतित है।
- क्योंकि 7,000 किलोमीटर से अधिक शत्रुतापूर्ण सीमाओं और बचाव के लिए संप्रभु हवाई क्षेत्रों की विशाल मात्रा को देखते हुए, 4.5 पीढ़ी के राफेल के दो स्क्वाड्रन हमारी वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- ऐसे में चीन को सैन्य रूप से दूर रखने के लिए, 4.5-पीढ़ी की सूची को मजबूत करने के लिए मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) की कमी को तत्काल पूरा करना, न केवल IAF की आवश्यकता है, बल्कि कई कारणों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है।

## भारत को अपनी वायु क्षमता बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए?

- उल्लेखनीय है कि पहले से ही विलंबित भारत के पांचवीं पीढ़ी के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) को सेवा में शामिल होने में एक दशक लगने की उम्मीद है। तब तक, चीन अमेरिका के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए पहले से ही अपना छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित कर चुका होगा। आने वाले वर्षों में जब तक तेजस Mk 1A, Mk 2 और AMCA का पूर्ण

पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, तब तक चीन इस क्षेत्र में वायु शक्ति और सैन्य संतुलन को अपने पक्ष में अपूरणीय रूप से बदल चुका होगा।

- इस प्रकार, लंबे समय से लंबित 114 मध्यम बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की आवश्यकता को तत्काल पूरा करना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता है।
- बड़ी संख्या को देखते हुए, भारत में अतिरिक्त संयुक्त रूप से उत्पादित राफेल के लिए फ्रांस के साथ द्विपक्षीय साझेदारी, साथ ही लड़ाकू विमान और इसके हथियारों के भविष्य के 4.5+ पीढ़ी वेरिएंट पर संयुक्त उन्नयन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहुंच के लिए एक दीर्घकालिक समझौता, रणनीतिक रूप से समझदारी भरा है।
- इससे एक विश्वसनीय भागीदार से लगातार और स्थिर पूर्ति संभव होगा, लड़ाकू विमानों की अधिक समानता सुनिश्चित होगी, भविष्य के लड़ाकू विमानों और हथियारों के उन्नयन और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के लिए भविष्य के इंजन विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- यह स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देते हुए इन्वेंट्री को संतुलित करेगा, रूस पर निर्भरता को कम करेगा और मनमौजी अमेरिकी सैन्य उद्योग पर निर्भरता को रोकेगा।

# भारत रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित 'प्रोजेक्ट नेक्सस':

## चर्चा में क्यों है?

- भारतीय रिज़र्व बैंक और चार आसियान देश "प्रोजेक्ट नेक्सस" पर सहयोग कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तेज़ भुगतान प्रणालियों को जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान के लिए एक मंच स्थापित करना है।

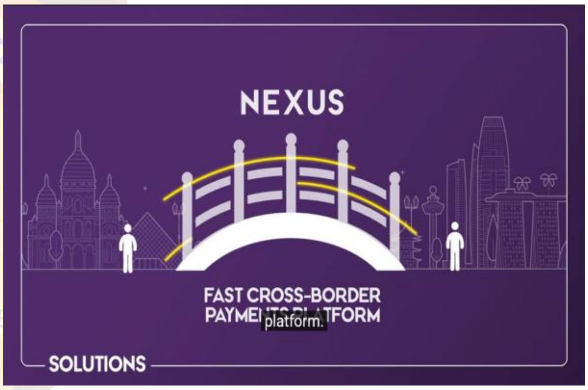


- भारत मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हो गया है, जिसकी योजना 2026 तक वैश्विक स्तर पर विस्तार करने, दक्षता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में लागत कम करने की है। इंडोनेशिया, जो आरंभिक चरणों से ही इस प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, एक विशेष पर्यवेक्षक है।

## प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है?

- प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (IPS) को जोड़कर त्वरित सीमा-पार भुगतान को बढ़ावा देना है। यह

भुगतान क्षेत्र में लाइव कार्यान्वयन की ओर बढ़ने वाली पहली BIS इनोवेशन हब की एक परियोजना है।

- आज 70 से ज्यादा देशों में घरेलू भुगतान कुछ ही सेकंड में अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं और प्रेषक या प्राप्तकर्ता को लगभग शून्य लागत का भुगतान करना पड़ता है। यह त्वरित भुगतान प्रणालियों (IPS) की बढ़ती उपलब्धता के कारण संभव हुआ है। इन IPS को एक-दूसरे से जोड़ने से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक 60 सेकंड के भीतर सीमा पार भुगतान संभव हो सकता है (ज्यादातर मामलों में)।

## प्रोजेक्ट नेक्सस के क्या लाभ हैं?

- प्रोजेक्ट नेक्सस को IPS के एक-दूसरे से जुड़ने के तरीके को मानकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भुगतान प्रणाली ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक नए देश के लिए कस्टम कनेक्शन बनाने के बजाय, ऑपरेटर नेक्सस प्लेटफ़ॉर्म पर एक कनेक्शन बना सकता है।
- यह एकल कनेक्शन एक तेज़ भुगतान प्रणाली को नेटवर्क पर अन्य सभी देशों तक पहुँचने की अनुमति देता है। नेक्सस तत्काल सीमा-पार भुगतान के विकास को महत्वपूर्ण रूप से तेज़ कर सकता है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार जबकि तीव्र भुगतान प्रणालियों की द्विपक्षीय कनेक्टिविटी से भारत और उसके साझेदार देशों को लाभ हो सकता है, वहीं बहुपक्षीय दृष्टिकोण से घरेलू भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा।
- आरबीआई ने पिछले एक साल में कई बार कहा है कि सीमा पार लेन-देन की मौजूदा लागत बहुत ज्यादा है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि सिस्टम पर कुछ संस्थाओं का दबदबा है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, सीमा पार छोटे प्रेषण लेन-देन 6% दर पर होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दर है।

## बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) क्या है?

- 1930 में स्थापित, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) स्वामित्व दुनिया भर के 63 केंद्रीय बैंकों के पास है, जो संयुक्त रूप से विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 95% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इसका मुख्यालय बेसल, स्विट्जरलैंड में है और इसके दो प्रतिनिधि कार्यालय हैं: हांगकांग एसएआर और मैक्सिको सिटी में, साथ ही दुनिया भर में इनोवेशन हब सेंटर भी हैं।

- BIS का मिशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की खोज का समर्थन करना और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करना है।
- **अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, यह केंद्रीय बैंकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:**
  - ➢ संवाद और व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच
  - ➢ जिम्मेदार नवाचार और ज्ञान-साझाकरण के लिए एक मंच
  - ➢ मुख्य नीतिगत मुद्दों पर गहन विश्लेषण और अंतर्दृष्टि मजबूत और प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवाएँ

# MCQ

**Q.1.** चर्चा में रहे 'दिल्ली की जलजमाव और बढ़ती बाढ़ की घटनाओं' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अनियंत्रित और बिना सोचे-समझे किया गया शहरी विस्तार दिल्ली में लगातार शहरी बाढ़ का मुख्य कारण है।
2. दिल्ली के शहर नियोजन संसाधन के रूप में पानी की लगातार उपेक्षा की गई है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**Ans. (c)**

**Q.2.** दिल्ली के तेज़ शहरी विस्तार की स्थिति के संदर्भ में नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी के डेटा के अनुसार, 1991 से 2011 तक दिल्ली का भौगोलिक आकार लगभग कितना हो गया है?

(a) दोगुना

(b) तीन गुना

(c) चार गुना

(d) पांच गुना

**Ans. (a)**

**Q.3.** चर्चा में रहे चीन के 'J20 माइटी ड्रैगन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. चीन ने हाल ही में तिब्बत में अग्रिम बेस पर इनकी तैनाती की है।

2. यह चीन का एक प्रमुख फाइटर प्लेन है, जो राफेल का प्रतिस्पर्द्धी माना जाता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

**Ans. (a)**

**Q.4.** उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक और चार आसियान देश "प्रोजेक्ट नेक्सस" पर सहयोग कर रहे हैं। निम्नलिखित आसियान देशों में कौन-सा इन चार आसियान देशों में शामिल **नहीं** है?

(a) सिंगापुर

(b) मलेशिया

(c) थाईलैंड

(d) इंडोनेशिया

**Ans. (d)**

**Q.5.** चर्चा में रहे 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. BIS का स्वामित्व दुनिया भर के 63 केंद्रीय बैंकों के पास है, जो संयुक्त रूप से विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 70% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. BIS का मिशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की खोज का समर्थन करना है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

**Ans. (b)**